आईटी विभाग ने तैयार किया मसौदा, इसे जल्द कैबिनेट से पास कराने की तैयारी

अब आईटी क्षेत्र को उद्योग का दर्जा

पहल

■ अजित खरे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के आईटी सेक्टर को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जल्द योगी सरकार जल्द इस सेक्टर को उद्योग का दर्जा देगी। इससे राज्य में निवेश कर रही मौजूदा कंपनियों व आने वाली कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। आईटी सेक्टर से जुड़ी तमाम परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ेगी। साथ ही विदेशी व दूसरे राज्यों की आईटी कंपनियां राज्य के अलग अलग हिस्सो में और निवेश के लिए प्रेरित होंगी।

आईटी विभाग ने इस संबंध में एक मसौदा तैयार किया है। जल्द इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। उद्योग का दर्जा मिल जाने से औद्योगिक प्राधिकरण आईटी पार्क व अन्य परियोजनाओं के लिए भी जमीन का बंदोबस्त करेंगे और उन्हें उन्हीं दर पर जमीन उपलब्ध होगी जिस दर पर दूसरे उद्योगों को मिलती है।

अभी उद्योग का दर्जा न होने के कारण आईटी सेक्टर को जमीन के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। इसके अलावा आईटी क्षेत्र में निवेश कर रही कंपनियों को औद्योगिक दर पर बिजली मिलेगी। यह और वह भी आसानी से उपलब्ध होगी। आईटी सेक्टर में वैसे भी बिजली की खपत भी काफी होती है।

सूत्रों के मुताबकि उद्योग का दर्जा मिलने के बाद आईटी कंपनियों को बिजली खर्च पर 20 प्रतिशत का फर्क पड़ेगा। उन्हें अलग इंडस्ट्रियल फीडर से निर्बाध बिजली मिलेगी। अभी आईटी कंपनियों को कार्मिश्यल रेट पर बिजली देनी पड़ती है। जो काफी महंगी होती है। उद्योग का दर्जा मिलने पर आईटी कंपनियों का सस्ती, अच्छी गुणवत्ता की पावर सप्लाई की आपूर्ति होगी सकेगी। कर्नाटक पहला ऐसा राज्य है जिसने आईटी सेक्टर को सबसे पहले उद्योग का दर्जा दिया था और आज उसने पूरे देश में आईटी सेक्टर में सबसे बड़ी छलांग लगाई है। तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश ने इसी तरह की रणनीति बनाई।

यह होंगे लाभ

तमाम तरह के टैक्स में रियायत मिलना संभव होगा। आईटी कंपनियों को पंजीकरण से लेकर लाइसेंस तक में राहत मिलेगी। तमाम औपचारिकताओं को आसानी पूरा किया जा सकेगा। आईटी पार्क, डाटा पार्क, टेक्नालॉजी पार्क, साफ्टवेयर पार्क, आईटी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के लिए आधारभूत ढांचा विकसित हो सकेगा। अपेक्षाकृत कम दरों पर ब्याज के साथ साथ बैद्धिक संपदा को आसानी से संरक्षित किया जा सकता है।

डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मिली पर्यावरणीय अनुमति

लखनऊ। केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लखनऊ , कानपुर, अलीगढ़, झांसी व चित्रकूट में विकसित किए जा रहे रक्षा गलियारे को अनुमति दे दी है। यूपीडा इन गलियारों को विकसित कर रहा है। लखनऊ के सरोजनीनगर में 164 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रक्षा गलियारे को विकसित किया जा रहा है। यहां जब रक्षा निवेश कंपनियों को प्लाट आवंटित होंगे तो यहां 33 प्रतिशत जमीन पर ग्रीन बेल्ट विकसित की जाएगी। यूपीडा को सुनिश्चित करना होगा कि यहां ग्रीन कवर विकसित किया जाए और कोई पेड़ कटने न पाए।

यूपीडा ने बताया है कि रक्षा उद्योग लगने पर रोजाना जो बायोडिग्रेडेबल कचरा, प्लास्टिक कचरा, अन्य कचरा व ई-कचरा निकलेगा, उसके निस्तारण की भी पर्याप्त उपाए किए गए हैं। इसी तरह के पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण रोकने के उपाय कानपुर, अलीगढ़, झांसी व चित्रकूट रक्षा गलियारे में किए जा रहे हैं।

सैमसंग व एलजी कंपनी को मिलेगा वित्तीय प्रोत्साहन

लखनऊ। यूपी सरकार ने आईटी कंपनी सैमसंग इंडिया व एलजी इलेक्ट्रानिक्स कंपनी को राज्य में निवेश करने के एवज में 1751 करोड़ रुपये -1751 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है और पिकप को इस संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए कहा है।

इस संबंध में शुक्रवार को औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने आदेश जारी किया। इनकी विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इन्हें वित्तीय प्रतिपूर्ति की जगह प्रोत्साहन दिया जाए।